

13/05/36

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेस हुई।
 प्रकरण के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक पार्शना-पत्र आम जनता की वरफ से पैसावर निवेदन किया गया कि ग्राम भीष्मपुर पंचसहरनगर, बहालील कसौली की आराजी खसरा नम्बर 1383/1 से 1383/9 की भूमि कृषि भूमि वर्ग रिपोर्ट है, जिसे बिना संपरिवर्तन करामे आवासीय उपयोग में ली जाकर प्लॉट बाने जा रहे है, इस कारण उनके खिलाल बानेवाही की जावे। पार्शना-पत्र के अवलोकन उपरान्त पार्शना-पत्र को अन्तर्गत धारा-177 राजस्मान काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत वर्ग रजिस्टर किया गया।

2/11
 उपसचिव अधिकारी
 कसौली (राज.)

सर्व संविधान सभा के सदस्यों को सूचित किया गया कि असाधारण सभा की सलाह किमा गया। असाधारण सभा के सभासदों ने जवाब देकर निर्देश किया गया कि हमारे पास सं. नं. 1383/1 व 1383/3 में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्माण नहीं किया गया है। असाधारण सभासदों व मोहनलाल ने निर्देश किया कि 1383/2 की रजिस्ट्री केनीकट हो चुकी है। 1383/4 की भी रजिस्ट्री हो चुकी है। निम्नी तरकीब रही है। कुछ सभ्य 24 बीघा भी, जो मोहनलाल शर्मा के नाम थी, जिसमें से 20 बीघा का बिस्वा बिश्व कर की गई है। बाकी 4 बीघा का बिस्वा भूमि बची है। यदि बिस्वा की गई जमीन वालों ने अर्थ कर किस ठे लो इसको नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। और वही निम्ने पार है। हमारा सं. नं. अला है। असाधारण सं. 2 व 13 ने जवाब देकर अवगत कराया कि 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/7, 1383/8, 1383/9 में दिल्ली उच्च न्यायालय का कोई निर्माण नहीं किया गया है, ना ही कोई भूमंड बनाकर मुहंटेया मांगी है। उम्ह अवसरानभर मौके पर खाली पड़े हैं। असाधारण सं. 5, संविधान सभासदों ने अपना जवाब देकर निर्देश किया कि 1383/9 में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। बल्कि

2/11/51

01/2026

गोरे पर पारल कलाई चल रही है। उम्ह प्राचीन
 जन के संबन्ध में लेण्डहोल्डर्स 102 करोड़ी से
 वर्तमान गोरा रिपोर्टे लबब की गई। वृहसी नकार करोड़ी
 द्वारा आपने पत्राक 157 दिनांक 29.4.2026 से
 गोरा रिपोर्टे वर्तमान पेश की। जिसमे स्पष्ट किया
 गया कि उनवान आम जनता बनाम सरकार व अन्य
 मुकदमा नंबर 1/26 न्यायालय राज्या में विचाराधीन
 पुस्तक क्र. न. 1383/1 लगा. 1383/9 सी जॉन्च करने
 पर उम्ह क्र. न. की भूमि मोडे पर म्वाली पड़ी है।
 सभतलीकरण का कार्य पूर्व में होना पाया गया। किसी
 प्रकार की मुद्दी गडी होना उम्ह क्र. न. में नही पाया
 गया। मोडे पर किसी प्रकार की मुद्दी गडी होना नही
 पाया गया। उपरोक्तापुकार अन्तिम बहस टेव निर्धारित
 दिवस को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान पक्षकारान म्वालेंदारे द्वारा मफ्त
 पूर्व में पेश जवान के तथ्यों को ही कोहरामा गया व
 लिखित बहस भी पेश की गई। पैरोकार सरकार ने
 भी बहस के दौरान अपने जवान के तथ्यों को
 कोहराले हुये वर्तमान में विवाहित माराजी का कोई
 और क्वि उपभोग नही होना प्रवगत कराया। उपरोक्त
 समस्त तथ्यों, बहस, जवान, पैरोकार सरकार का

9/11/26

आम जनता व सरकार व अन्य (6)
01/2021

जवान व बरस के आधार पर इस प्रार्थना
पत्र का निस्तारण किया जाना-नामौजित
है। उभयपक्ष जवान व बरस से स्पष्ट है
कि विवाहित महिला का वहीमान में कोरे गैर
कृषि उपयोग नहीं हो रहा है तथा मोके पर
हाथि कार्य हो किया जा रहा है।

उपर्युक्त समस्या तथो, जवान, बरस
पैरोकार सरकार का जवान व बरस के आधार
पर उक्त प्रार्थना-पत्र को निस्तारित करते
हुए इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है तथा RDR करौली को निर्दिष्ट किया
जाता है कि समस्त खालेशरों को बिना
किसी संपरिवहन करामे गैर कृषि कार्य हेतु
पाबंद करे। पभावली इसी स्तर पर पैसल
सुमार होकर नंबर से कम होकर शामिल
दफ्तर है। निर्वास खुले नमामालम में सुवास
गमा।

2/11
मुखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)